[2009] 4 एस. सी. आर. 457

कृष्णा राम

बनाम

राजस्थान राज्य

2001 की आपराधिक अपील संख्या 402

17 मार्च, 2009

[लोकेश्वर सिंह पंता और बी. सुदर्शन रेड्डी, जेजे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) और धारा 20 -मांग और स्वीकृति के लिए अभियोजन अवैध संतुष्टि-आरोपियों के कब्जे से दागी रकम बरामद- ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी-उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि -अपील पर, माना गया: दोषसिद्धि उचित - अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति साबित हुई -अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य सुसंगत और विश्वसनीय हैं-आरोपियों के कब्जे से एक बार पैसे की बरामदगी साबित हो गया, धारा 20 के तहत अनुमान का बोझ उस पर डाल दिया गया अभियुक्त और अभियुक्त उस अनुमान का खंडन करने में विफल रहे।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 378-दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील का दायरा-निर्णय, यदि दो विचार संभव हैं, एक दोषमुक्ति के लिए और दूसरा दोषसिद्धि के लिए,अपीलीय अदालत को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से अभियुक्त के अपराध का एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष न निकले।

अपीलकर्ता-अभियुक्त पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी नहीं पाया और इसलिए उसे बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया ।

इसलिए वर्तमान अपील। अपील को ख़ारिज करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया :

1.1 रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित और विकृत है और उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश में सही हस्तक्षेप किया है और अपीलकर्ता को धारा 7 और 13(1) (डी) के साथ धारा 13 (डी) के तहत दोषी ठहराया है। 2) भ्रष्टाचार निवारण का अधिनियम, 1988.[पैरा 11] (446-सी-डी)

कल्याण सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2006) 13 एससीसी 303; टी सुब्रमण्यन बनाम टीएन राज्य, (2006) 1 एससीसी 401; राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, पुदुकोट्टई, टीएन द्वारा किया गया। वी. ए. बी पार्थिबन (2006) 11 एससीसी 4 73 - संदर्भित।

1.2 शिकायतकर्ता को भूमि के स्थायी पट्टा धारक अधिकार प्रदान करने के संबंध में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत राशि के रूप में रुपये 5001/-की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता का साक्ष्य सुसंगत और आरोप योग्य पाया गया है। उनके साक्ष्य तैयार किए गए समसामयिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं, जांच अधिकारी द्वारा पैसे देने से पहले अपीलकर्ता को सौंप दिया गया, शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के इस सुझाव का जोरदार खंडन किया कि ऋण राशि के पुनर्भुगतान के रूप में DW-1 द्वारा अपीलकर्ता को रुपये 5001/- भेजे गए थे। शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और अन्य गवाह जो एंटी करप्शन टीम द्वारा अपीलकर्ता को रंगे हाथों पकड़े जाने के समय मौजूद थे, उनसे बचाव पक्ष द्वारा लंबी जिरह की गई है, लेकिन उनके साक्ष्य से ऐसा कुछ भी ठोस नहीं निकला है जिससे संदेह की कोई छाया पैदा हो, कि वे सच्चे गवाह नहीं हैं। उन्होंने अपराध का विश्वसनीय और सुसंगत संस्करण दिया है और उनके साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं। [पैरा 9] [465-एफ-जी-एच; 466-ए]

1.3. एक बार जब यह साबित हो जाए कि पैसा अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किया गया था, पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अनुमानित अनुमान का बोझ अपीलकर्ता पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे वह अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के माध्यम से या विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश करके यह साबित नहीं कर सका कि DW-1 ने अपीलकर्ता को ऋण के रूप में रुपये 500/-दिए थे शिकायतकर्ता के माध्यम से । [पैरा 9] [464-एच; 465-ए]

1.4. DW-1 ने कोई कारण नहीं बताया है कि जिस दिन उसे एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया था, उस दिन अपीलकर्ता को 5001 रुपये की राशि देने के लिए उसने शिकायतकर्ता को अकेले क्यों चुना। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संभावित और उचित नहीं था। [पैरा 9] [465-ए-बी]

केस कानून संदर्भ

(2006) 13 एससीसी 303	**पैरा 6**	**में संदर्भित**
(2006) 1 एससीसी 401	**पैरा 6**	**में संदर्भित**
(2006) 11 एससीसी 473	**पैरा 10**	**में संदर्भित**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील क्रमांक 402/2001, दिनांक 22.12.2000/12.01.2001 के निर्णय एवं आदेश से राजस्थान उच्च न्यायालय की, आपराधिक अपील संख्या 673/1999.

मनोज प्रसाद, ल्शार सिंह, के.के. श्रीवास्तव, जनेश सिंह, अपीलकर्ता के लिए.

प्रतिवादी की ओर से मनीष सिंघवी, एएजी, मिलिंद कुमार, अरुणेश्वर गुप्ता।

कृष्णा राम बनाम राजस्थान राज्य

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया - लोकेश्वर सिंह पांटा, न्यायमूर्ति.

1. यह अपील दिनांकित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न हुई है, 22.12.2000 राजस्थान उच्च न्यायालय, खंडपीठ द्वारा पारित एकलपीठ आपराधिक अपील संख्या 673 /1999 में जोधपुर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश को निरस्त कर दिया है अभियुक्त को बरी कर दिया गया और उसे निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया, धारा 7 और 13(1)(डी) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पढ़ा जाए [संक्षेप में "पीसी अधिनियम, 1988"] और उसे एक वर्ष के लिए कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। 500/- रूपये का जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षिप्त तथ्य, जिसके कारण अभियुक्त पर मुकदमा चलाया गया, इस प्रकार हैं:

2.1] कृष्ण राम - आरोपी-अपीलकर्ता यहां वर्ष 1991 में पटवारी के रूप में तैनात थे और राजस्व सर्कल 84 आरबीबी तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर के प्रभारी थे। 20.03.1991 को, गुरमुख सिंह-शिकायतकर्ता [पीडब्लू-2], निवासी 85, आरबी ने राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो (एसबी) गंगानगर पोस्ट का दौरा किया और हजारी लाल [पीडब्लू-8], इंस्पेक्टर चौकी प्रभारी को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि वह अस्थाई खेती पट्टे के आधार पर चक 85 आरबी में 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि तथा लाखा टीबा में 12.5 बीघा भूमि का धारक है।वह अपने अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तित करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपेक्षित आवेदन पत्र (प्रदर्शनी पी7) भरा और उसे श्री जगमाल सिंह [पीडब्लू-9], उप-विभागीय अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने बाद में उसे चिह्नित किया। यह तहसी/दार को, रायसिंहनगर और परिवादी को मूल आवेदन सौंपा। तहसीदार ने आवेदन को संबंधित पटवारी के पास भेज दिया।

2.2] 18.03.1991 को, पीडब्लू-2 ने अपीलकर्ता (पटवारी) से संपर्क किया और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आवेदन (उदा.-पी-7) प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने स्थायी पट्टा धारकों के अधिकारों पर उसे भूमि आवंटन के संबंध में उसके (शिकायतकर्ताओं) पक्ष में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत राशि के रूप में 1,000/-रुपये की मांग की थी। पीडब्लू-2 ने अपीलकर्ता से अनुरोध किया कि उसके पास उसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, जिस पर अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को उसके द्वारा मांगे गए 1,000/- रुपये के बजाय 500/- रुपये की राशि के साथ उसके घर आने के लिए कहा। एक पूर्व अवसर. शिकायतकर्ता द्वारा यह भी कहा गया था कि वह अपीलकर्ता को रिश्वत की रकम देने को तैयार नहीं था और अवैध परितोषण की मांग करने के लिए उसे पुलिस द्वारा पकड़वाना चाहता था और केवल इसी उद्देश्य से शिकायत दर्ज की गई थी (उदा.-पी-13)) पीडब्लू-8 हजारी लाल-इंस्पेक्टर, चौकि, गंगानगर के ब्यूरो प्रभारी के सामने पेश किया गया। शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त होने पर, पीडब्लू-8 ने यूआईटी, गंगानगर के कर्मचारियों आसकरण (पीडब्लू-1) और राजे राम (पीडब्लू-3) को बुलाया, जिन्हें शिकायतकर्ता से मिलवाया गया और उन्हें शिकायत का पूरा सार बताया गया। दोनों गवाह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के खिलाफ प्रस्तावित ट्रैप कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को भुगतान के लिए 100/- रुपये मूल्यवर्ग के चार करेंसी नोट और 50/- रुपये मूल्यवर्ग के दो नोट, यानी कुल 500/- रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद

ब्यूरो के कर्मचारियों ने करेंसी नोटों को फिनोलफथेलिन पाउडर से उपचारित किया, जो शिकायतकर्ता की शर्ट की बाईं ओर की जेब में रखे गए थे। निर्देश दिए गए कि अब पैसे को न छूएं और अपीलकर्ता की मांग पर उसे सौंप दिया जाएगा।शिकायतकर्ता की शिकायत प्राप्त होने पर, पीडब्लू-8 ने यूआईटी, गंगानगर के कर्मचारियों आसकरण (पीडब्लू-1) और राजे राम (पीडब्लू-3) को बुलाया, जिन्हें शिकायतकर्ता से मिलवाया गया और उन्हें शिकायत का पूरा सार बताया गया। दोनों गवाह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के खिलाफ प्रस्तावित ट्रैप कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को भुगतान के लिए 100/- रुपये मूल्यवर्ग के चार करेंसी नोट और 50/- रुपये मूल्यवर्ग के दो नोट, यानी कुल 500/- रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद ब्यूरो के कर्मचारियों ने करेंसी नोटों को फिनोलफथेलिन पाउडर से उपचारित किया, जो शिकायतकर्ता की शर्ट की बाईं ओर की जेब में रखे गए थे। निर्देश दिए गए कि अब पैसे को न छूएं और अपीलकर्ता की मांग पर उसे सौंप दिया जाएगा। शिकायतकर्ता को अपीलकर्ता को पैसे का भुगतान करने के तुरंत बाद अपनी पगड़ी पर हाथ रखकर फंसाने वाली पार्टी के सदस्यों को संकेत देने के लिए कहा गया था। गवाहों को शिकायतकर्ता के करीब खड़े होने का भी निर्देश दिया गया ताकि पुलिस पार्टी अपीलकर्ता को रंगे हाथों पकड़ सके। इसके बाद, ट्रैपिंग पार्टी रायसिंहनगर में गुलबाड़ीवाली हवेली के पास पहुंची, जहां अपीलकर्ता रहता था। अपीलकर्ता उस समय अपने घर में दो या तीन व्यक्तियों के साथ बैठा था, लेकिन शिकायतकर्ता ने उसे घर की पहली मंजिल पर कमरे के बाहर आने के लिए कहा और फंसाने वाले पक्ष के सदस्य नीचे खड़े रहे। इसके बाद, शिकायतकर्ता से संकेत मिलने पर, ट्रैपिंग पार्टी के सदस्य तुरंत अपीलकर्ता के पास पहुंचे, जहां पीडब्लू-8 ने वहां मौजूद गवाहों की उपस्थिति में उससे सवाल किया कि क्या उसने शिकायतकर्ता गुरमुख सिंह से 500/- रुपये रिश्वत के रूप में स्वीकार किए थे। अपीलकर्ता का पहला संस्करण यह था कि गुरमुख सिंह ने उसे भूमि आवंटन के लिए अपने आवेदन पर अनुकूल रिपोर्ट बनाने के लिए 500/- रुपये दिए थे, लेकिन फिर वह झिझक गया और पलट गया और जवाब दिया कि 500/- रुपये उसे दिए गए थे। ऋण। हमें दिया गया। मात्रा। शिकायतकर्ता ने दोहराया कि अपीलकर्ता की मांग पर उसने रुपये दिये थे. अपना काम करने के लिए अपीलकर्ता को अवैध परितोषण के रूप में 500/- रु. उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने राशि स्वीकार कर ली थी और नोटों को गिनने के बाद उन्होंने उन्हें अपनी शर्ट की बाईं ओर की जेब में रख लिया। पुलिस कांस्टेबल ने तुरंत अपीलकर्ता की दोनों कलाई पकड़ ली और अपीलकर्ता के हाथ का घोल भी गुलाबी हो गया। अपीलकर्ता को अपनी शर्ट की जेब से पैसे निकालने के लिए कहा गया और नोटों की गिनती करने पर वे वही पाए गए जो शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को भुगतान किए गए थे। लेकिनअपीलकर्ता की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उसकी जेब से रिश्वत के 500/- रुपये के अलावा 227/- रुपये की राशि भी मिली। अपीलकर्ता की बुशशर्ट को सोडियम घोल में डुबोया गया था कार्बोनेट जो गुलाबी भी हो गया और अंदर ले लिया गयासबूत के तौर पर. अपीलकर्ता से संबंधित अभिलेख भी कब्जे में ले लिए गए। अपीलकर्ता के कब्जे वाले कमरे की तलाशी लेने के बाद, एक साइट योजना तैयार की गई। साक्ष्य के तौर पर जब्त की गई सामग्री को मालखाने में रखा गया। अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर (एक्स पी-16) तैयार की गई और दर्ज की गई जयपुर स्थित मुख्यालय के पुलिस स्टेशन में। नमूना बोतलें फोरेंसिक प्रयोगशाला, जयपुर भेजी गईं और रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-17) प्राप्त होने पर और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया अदालत में।

2.3] सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने कम से कम दस गवाहों से पूछताछ की और प्रदर्शन के तौर पर 19 दस्तावेज़ और 12 लेख पेश किए। अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में अपराध के कमीशन में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने दलील दी कि किसी गोराई के खेत से एक पेड़ की कटाई के संबंध में कुछ विवाद था, जो अपीलकर्ता के मौके पर निरीक्षण करने पर शिकायतकर्ता के खेत में पड़ा हुआ पाया गया और, इसलिए, इसी पृष्ठभूमि में शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को झूठे मामले में शामिल करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने अपने बचाव में रामचन्द्र (डीडब्ल्यू-1) की जांच की और डी-1 तथा डी-2 के रूप में दो दस्तावेज प्रदर्शित किये।

3.विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने, रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण पर, अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत आरोपों का दोषी नहीं पाया, और तदनुसार उसे बरी कर दिया गया।

4. राजस्थान राज्य ने अपीलकर्ता के बरी होने से असंतुष्ट होकर एस.बी. को प्राथमिकता दी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में आपराधिक अपील संख्या 1999। निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2000 द्वारा, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को धारा 7 और 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत अपराध का दोषी ठहराया, 1988 के पीसी अधिनियम के तहत और उस पर उपरोक्त सजा लगाई गई।

5. इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता इस अपील के माध्यम से हमारे सामने है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री मनोज प्रसाद ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी करने के तर्कसंगत आदेश को उलटने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण कानून की दृष्टि से गलत है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपील। तर्कों के समर्थन में, का/यान सिंह बनाम एमपी राज्य [(2006) 13 एससीसी 303] और टी सुब्रमण्यम बनाम टीएन राज्य में इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया गया है। ((2006) 1 एससीसी 401]। हम उक्त निर्णयों से गुजर चुके हैं। कानून के स्थापित प्रस्तावों के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है कि यदि सबूतों के मूल्यांकन और प्रासंगिक उपस्थित परिस्थितियों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि दो विचार संभव हैं, एक जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने बरी करने के लिए रखा है। ऐसे में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए आरोपी और अन्य स्थिति, विवेक के नियम को उच्च न्यायालय का मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के आदेश को परेशान करने के लिए। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि जहां रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपी के अपराध के एकमात्र और अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाती है, तो बरी करने के फैसले में अपीलीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन उचित संदेह से परे यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की कोई मांग की थी, जैसा कि उसके द्वारा

आरोप लगाया गया था और इसलिए, पी.सी. की धारा 20 के तहत विचार किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1988 को गलत तरीके से अपीलकर्ता के खिलाफ और अभियोजन पक्ष के पक्ष में लागू किया गया है। इस प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, टी. सुब्रमण्यम बनाम टी.एन. राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। [(2006) 1 एससीसी 401]। उपरोक्त उद्धृत मामले में यह न्यायालय, धारा 5(1)(डी) के साथ पठित धारा के तहत अपराध के लिए अभियुक्तों के मामले पर विचार करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) में माना गया है कि आरोपी ने सबूतों के आधार पर उचित और संभावित स्पष्टीकरण की पेशकश की थी कि पैसा उसके द्वारा पट्टा किराया बकाया के रूप में स्वीकार किया गया था, न कि अवैध परितोषण के रूप में।

8. कानून के उपरोक्त स्थापित प्रस्तावों के आलोक में, हमने यह पता लगाने के लिए वर्तमान मामले में साक्ष्यों की स्वतंत्र जांच की है कि क्या अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा जा सकता है या नहीं।

9. गुरमुख सिंह (पीडब्लू-2) ने रिकॉर्ड पर साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता की मांग पर, उसने स्थायी आवंटन के लिए तहसीलदार द्वारा अपीलकर्ता को चिह्नित आवेदन पर अनुकूल रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उसे अवैध परितोषण के रूप में 500/- रुपये का भुगतान किया था। , शिकायतकर्ता को पट्टे का भुगतान किया था। घटना के दिन, 100/- रुपये मूल्यवर्ग के चार करेंसी नोट और 2/- रुपये मूल्यवर्ग के दो करेंसी नोट पीडब्लू-2 द्वारा अपीलकर्ता को सौंपे गए थे, जिसे सौंपने से पहले फँसाने वाले पक्ष द्वारा उसका इलाज किया गया था। फेनोल्फथेलिन पाउडर। ट्रैपिंग पार्टी ने अपीलकर्ता की बुशशर्ट की जेब की तलाशी लेने के बाद, उसके निजी कब्जे से वे मुद्रा नोट बरामद किए। सबसे पहले, अपीलकर्ता ने अपना अपराध कबूल कर लिया था, लेकिन तेजी से ठीक होने के बाद, उसने अपना रुख बदल दिया और जांच अधिकारी को बताया कि यह पैसा शिकायतकर्ता ने उसे DW-1 की ओर से ऋण राशि के रूप में सौंपा था। यह DW-1 का साक्ष्य है कि प्रश्नगत पैसे को छोड़कर, उसके और अपीलकर्ता के बीच कभी भी पैसे का लेनदेन नहीं हुआ था। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि रु. घटना के दिन एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने अपीलकर्ता की शर्ट की जेब से 500/- रुपये बरामद किये थे। एक बार जब यह साबित हो जाता है कि पैसा अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद किया गया था, तो पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अनुमान का बोझ अपीलकर्ता पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे उसे अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के माध्यम से साबित करना होता है। खंडन नहीं कर सका या विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश करके यह साबित नहीं कर सका कि DW-1 ने रुपये दिए थे। शिकायतकर्ता के माध्यम से अपीलकर्ता को ऋण के रूप में 500/- रु, डीडब्ल्यू-1 राम चंद्र ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक टीम द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दिन उन्होंने अपीलकर्ता को 500/- रुपये की राशि देने के लिए अकेले शिकायतकर्ता को क्यों चुना। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संभावित और उचित नहीं था। अपीलकर्ता के कब्जे 500/- रुपये के मुद्रा नोट बरामद किए गए, जिन्हें गवाहों की उपस्थिति में पीडब्लू हजारी लाल-इंस्पेक्टर द्वारा फिनोलफथेलिन पाउडर के साथ इलाज किया गया था। ट्रैपिंग पार्टी के सदस्य शिकायतकर्ता के साथ रायसिंह नगर स्थित अपीलकर्ता के घर गए जहां शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि अपीलकर्ता को सौंपी गई। पीडब्लू-8 ने अपीलकर्ता को अपना परिचय दिया और उससे पूछा

कि क्या उसने रिश्वत की राशि स्वीकार की है। शिकायतकर्ता की ओर से अपीलकर्ता ने जवाब दिया कि यह रिश्वत नहीं थी, पैसा लेकिन ऋण चुकौती की राशि, शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह ऋण राशि नहीं बल्कि अपीलकर्ता द्वारा उससे मांगी गई रिश्वत राशि है। गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता ने अपनी शर्ट की जेब से 500/- रुपये के नोट निकाले। बरामद नोटों के नंबर शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता को सौंपने से पहले एसीबी कार्यालय में नोट कराए गए नंबरों से मेल खाते हैं। अपीलकर्ता द्वारा पहनी गई बुशशर्ट को सोडियम कार्बोनेट घोल में धोया गया और वह गुलाबी हो गई। रुपये की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के साक्ष्य। परिवादी को भूमि के स्थायी पट्टा धारक अधिकार प्रदान करने के संबंध में अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए अपीलार्थी द्वारा रिश्वत राशि के रूप में ली गई 500/- की राशि सुसंगत एवं निराधार पाई गई है। उनके साक्ष्य समसामयिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित हैं, पैसा देने से पहले जांच अधिकारी ने तैयार किया अपीलार्थी को सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता ने सहानुभूतिपूर्वक अपीलकर्ता के सुझाव का खंडन किया कि डीडब्ल्यू-1 द्वारा अपीलकर्ता को ऋण राशि के पुनर्भुगतान के रूप में 500/- रुपये भेजे गए थे। शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी और अन्य गवाह जो अपीलकर्ता उस समय उपस्थित था जब उसे भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था, बचाव पक्ष द्वारा उससे लंबी जिरह की गई, लेकिन उसके सबूतों से ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे यह संदेह पैदा हो कि वह सच्चा गवाह नहीं था। उन्होंने अपराध का एक विश्वसनीय और सुसंगत संस्करण दिया है और उनके साक्ष्य आत्मविश्वास को प्रेरित करते हैं।

10. *पुलिस निरीक्षक, पुडुकोट्टई, टीएन बनाम ए पार्थिबन [(2006) 11 एससीसी 473]* द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य में, इस न्यायालय ने माना है कि अवैध संतुष्टि की प्रत्येक स्वीकृति, चाहे मांग से पहले हो या नहीं, धारा 7 के अंतर्गत कवर की जाएगी। अधिनियम। लेकिन, यदि अवैध परितोषण की स्वीकृति लोक सेवक की मांग के अनुसरण में है, तो यह भी पीसी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के अंतर्गत आएगा।

11. ऊपर चर्चा किए गए संपूर्ण साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णयों पर सावधानीपूर्वक और बारीकी से विचार करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अनुचित और विकृत पाया गया है। और उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है और अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत दोषी ठहराया है।

12. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(डी) के तहत अलग से सजा देने के बजाय, अपने विवेक से एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी है। रुपये का अपीलकर्ता पर पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के तहत 500/- जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

13. अपीलकर्ता द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है। हम, इस प्रकार, किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण में कोई योग्यता और सार नहीं पाया गया अपीलकर्ता की ओर से ।

14. परिणाम में, उपरोक्त कारणों से, कोई नहीं है इस अपील में दम है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

15. आरोपी अपीलकर्ता जमानत पर है, जिसे इस न्यायालय ने 30 मार्च, 2001 के आदेश द्वारा प्रदान किया है। उसे मूल सजा के शेष भाग को पूरा करने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा।

के.के.टी. अपील खारिज।

PAGE NO 457 TO 466

Translated By:-

Nishant Singla

J.O. Code :- UP3819
Additional District & Session Judge
Fast Track Court No. 1
Muzaffarnagar (Uttar Pradesh)